अपनी छवि का ध्यान रखें क्योंकि इसकी आयु आपकी आयु से अधिक होती है।
– अज्ञात

कोई अच्छा संकेत नहीं

वैसे भी पिछले साल मार्च में जिस तरह से इसका गठन हुआ था, उससे खासकर उन लोगों में काफी निराशा फैली थी, जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया था और इसके बल पर देश के सिस्टम में बुनियादी बदलाव की उम्मीदें बांध रखी थीं।

नवीन जोशी।

अगले महीने लोकपाल के गठन को एक साल पूरे हो जाएंगे। पिछले एक साल के भीतर लोकपाल के कामकाज, इसकी अंदरूनी हलचल और इसके प्रति सरकार के रवैये को लेकर जो बातें मीडिया रिपोर्टों और अन्य स्रोतों से छन–छन कर आई हैं, उनसे इस संस्था के भविष्य को लेकर कोई अच्छा संकेत नहीं मिलता। वैसे भी पिछले साल मार्च में जिस तरह से इसका गठन हुआ था, उससे खासकर उन लोगों में काफी निराशा फैली थी, जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया था और इसके बल पर देश के सिस्टम में बुनियादी बदलाव की उम्मीदें बांध रखी थीं। अभी आलम यह है कि लोकपाल को अपना दफ्तर तक नहीं मिल पाया है।

आरटीआई के जरिये प्राप्त एक जानकारी के अनुसार भारत के लोकपाल का दफ्तर अशोक होटल, चाणक्यपुरी में है। इस होटल के 12 कमरों और 2 छोटे हॉल में यह चल रहा है और इसका हर महीने का किराया 50 लाख रुपये पड़ता है। जहां तक लोकपाल के कामकाज का प्रश्न है तो उसकी वेबसाइट के अनुसार 30 सितंबर 2019 तक उसे 1065 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 1000 का निपटारा कर दिया गया। इनमें ज्यादातर मामूली थीं और लोकपाल के दायरे में नहीं आती थीं। बाकी जो मामले बच गए हैं, उन पर नियम बनने के बाद कार्यवाही होगी। रहा सवाल इन नियमों की रचना का, तो लगता नहीं कि सरकार को इसकी कोई जल्दी है।

लोकपाल एक्ट का सेक्शन–59 कहता है कि लोकपाल के लिए नियम केंद्र बनाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने नोडल डिपार्टमेंट के रूप में इस नियमावली का एक मसविदा तैयार करके कानून मंत्रालय को भेज दिया था लेकिन वहां से इस बारे में अब तक कोई सूचना जारी नहीं हुई है।

कोई काम न होने को लेकर लोकपाल के एक सदस्य जस्टिस दिलीप बी भोसले ने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया, हालांकि इसके पीछे निजी वजहें बताईं। बाद में पता चला कि वे लोकपाल की निष्क्रियता से दुखी थे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस भोसले ने इस्तीफा देने से पहले लोकपाल चेयरमैन जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को तीन खत लिखे थे, जिनमें उन्होंने कई चीजों को लेकर शिकायत की थी और कामकाज को लेकर कुछ सुझाव भी दिए थे। मसलन यह कि जब तक बाकायदा काम शुरू नहीं हो जाता, तब तक के समय का उपयोग लोकपाल में शिकायतों का डिजिटाइजेशन करने और शिकायत की प्रक्रिया संबंधी नियम बनाने में किया जा सकता है। दूसरे पत्र में उन्होंने प्रशासनिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, खर्च, विजिलेंस आदि के लिए कमेटी गठित करने की मांग की थी। अपने तीसरे पत्र में उन्होंने बैठक की कार्यवाही को कुछ का कुछ दर्ज कर दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की थी।

बहरहाल, उनके सुझाव किसी काम नहीं आए। लोकपाल और सरकार, दोनों स्तरों पर दिख रही यह सुस्ती उनका टालू रवैया ही दर्शाती है। भ्रष्टाचार को लेकर सरकार गंभीर है तो उसे लोकपाल को सक्रिय और सक्षम बनाने के हर संभव प्रयास करने चाहिए।

भौतिक अस्तित्व

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

सिर्फ दो चीजों का अस्तित्व मौजूद है... एक वो जो हो रहा है। इसे हम भौतिक रचना के रूप में देखते हैं... और दूसरा है वह समय ... जिसके अंतर्गत वह रचना हो रही है। जो होना है... भले ही वह अच्छा–बुरा, छोटा–बड़ा... कैसा भी हो... वह होगा तो अपने समय से ही। भौतिक रचनाएं या स्थितियां समय पर निर्भर करती हैं और ये सभी अस्थायी होती हैं, और अस्थायी रचनाओं का उत्थान और पतन तो लगा ही रहता है। एक समय बाद "जो हो रहा है"... वह "जो हो चुका है" में तब्दील हो जाता है। महत्वपूर्ण चीज वह यात्रा या समय है, जिसके अंतर्गत वह अस्थायी भौतिक घटना घटित हुई है। यौगिक विद्या में इसे वास्तविकता, चेतना और सत्यता कहा गया है.... सामान्य भाषा में इसे "साक्षी" कहा जा सकता है, जिसने स्वयं हर चीज का अनुभव किया हो, उसे प्रमाणित किया हो।

संपादकीय

महंगाई की मार

तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई के मोर्चे पर नाकामी ही सरकार के हाथ आ रही है। खाने–पीने की चीजें महंगी होने से जनवरी में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7.59 फीसदी पर पहुंच गई, जो बीते 6 सालों का उच्चतम स्तर है। देश में खुदरा महंगाई दर मई 2014 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर चली गई है। यह लगातार छठा महीना है, जब महंगाई दर में बढ़ोतरी देखी गई है। इससे पहले दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 7.35 फीसदी रही थी। थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर भी जनवरी में बढ़कर 3.1 प्रतिशत हो गई है, जो इससे पहले वाले महीने में 2.59 प्रतिशत थी। महंगाई में यह इजाफा मुख्यतरू प्याज और आलू जैसी रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते हुआ है।

पिछले कुछ हफ्तों में आए आर्थिक आंकड़ों से ऐसा लग रहा था कि अर्थव्यवस्था अब सुस्ती से उबर रही है, लेकिन महंगाई और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों से एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के आंकड़ों के अनुसार जनवरी में खाद्य पदार्थों की खुदरा महंगाई दर 13.63 फीसदी रही। सब्जियों, दालों, मांस–मछली और अंडों के दाम में सबसे तेज बढ़ोतरी हुई। लगातार तीसरे महीने खाद्य खुदरा महंगाई दर दहाई अंक में रही है। नवंबर 2019 में यह 10.01 फीसदी और दिसंबर 2019 में 14.19 फीसदी थी। दूसरी तरफ देश के विनिर्माण क्षेत्र में नरमी रहने के कारण दिसंबर 2019 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 0.3 फीसदी की गिरावट आई। साल भर पहले इसी महीने में देश के औद्योगिक उत्पादन में 2.5 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। बहरहाल, खुदरा महंगाई दर बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह खाने–पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी है।

इस वर्ष के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के वास्तविक खर्च को देखें तो 31 अक्टूबर 2019 तक इसका मात्र 27 प्रतिशत हिस्सा ही वास्तव में खर्च हो पाया था।

कितना खर्च हुआ और कैसे

भारत डोगरा।

जब भी केंद्र और राज्य सरकारों के वार्षिक बजट प्रस्तुत किए जाते हैं तो प्रायः अधिक ध्यान नए वर्ष के लिए निर्धारित आवंटनों पर ही जाता है। यह महत्वपूर्ण पक्ष प्रायः उपेक्षित रह जाता है कि जो आवंटन पिछले वर्ष हुआ उसमें कितना खर्च हुआ और कैसे खर्च हुआ? इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए यदि हम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पिछले वर्ष 2019–20 के वास्तविक खर्च को देखें तो 30 नवंबर, 2019 तक इस बजट का 49 प्रतिशत ही खर्च हुआ था। इस वर्ष के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के वास्तविक खर्च को देखें तो 31 अक्टूबर 2019 तक इसका मात्र 27 प्रतिशत हिस्सा ही वास्तव में खर्च हो पाया था। बजट दस्तावेजों में वास्तविक खर्च के अनुमान बहुत देर से प्रस्तुत किए जाते हैं। अच्छा होगा कि पूरे पिछले वर्ष का नहीं तो पिछले 8 या 9 महीनों का वास्तविक खर्च ही बजट के दस्तावेजों में आ जाए। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह संभव है। लेकिन न तो ये आंकड़े सहज उपलब्ध होते हैं, न इन पर व्यापक चर्चा होती है। बजट दस्तावेजों में पिछले वर्ष के वास्तविक खर्च के स्थान पर संशोधित अनुमान (रिवाइज्ड एस्टिमेट या आर.ई.) प्रस्तुत किए जाते हैं। यह खर्च यदि मूल आवंटन से काफी कम हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वास्तविक खर्च में काफी कटौती हो रही है। यदि हम 2019 वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान को ही देखें तो सबसे चर्चित मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में बड़ी कटौती नजर आती है। इस मंत्रालय के लिए 2019–20 के बजट का मूल आवंटन 1,38,564 करोड़ रुपये था जबकि संशोधित अनुमान में लगभग 29,000 करोड़ रुपये की बड़ी कटौती कर इसे 1,09,750 करोड़ रुपये कर दिया गया।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में बड़ी कटौती हुई। इसका मूल आवंटन 3,745 करोड़ रुपये था, जिसे संशोधित बजट में 2,760 करोड़ रुपये पर सिमटा दिया गया। सबसे चर्चित स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रही है, जिसके लिए 75,000 करोड़ रुपये का मूल आवंटन था। इसे संशोधित बजट में 54,370 करोड़ रुपये पर ला दिया गया। बाजार हस्तक्षेप स्कीम और कीमत समर्थन स्कीम (एमआईएस–पीएसएस) के लिए मूल आवंटन 3000 करोड़ रुपये का था। यह संशोधित अनुमान में 2010 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना विभिन्न मंत्रालयों में बंटी हुई है। यदि इन सबका योग किया जाए तो पिछले बजट में इस योजना के लिए 9,843 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी, जो संशोधित अनुमान में 7,958 करोड़ रुपये पर सिमट गई। बागवानी (हॉर्टिकल्चर) के राष्ट्रीय मिशन के लिए 2,225 करोड़ की व्यवस्था थी, पर संशोधित अनुमान में यह राशि 1,584 करोड़ रुपये हो गई। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय की ये कटौतियां आश्चर्यजनक कही जाएंगी क्योंकि बीते दिनों में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य अत्यधिक चर्चा में रहा है।

मिड डे मील बाल–पोषण का चर्चित कार्यक्रम है। इसके लिए मूल आवंटन 11,000 करोड़ रुपये था पर संशोधित अनुमान में यह 9,912 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

सूडोकु नवताल-5254

सरल

5	9		1		2		3	8
			4		5			
2								5
		3		5		4	8	
	7						1	
	5	8		6		9		
8								1
			2		9			
3	4		6		7		5	2

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5253 का हल

4	6	2	3	5	8	9	1	7
8	1	7	9	2	6	3	5	4
3	5	9	1	7	4	8	2	6
6	4	1	5	3	7	2	8	9
2	7	5	8	4	9	6	3	1
9	3	8	2	6	1	4	7	5
1	2	3	6	9	5	7	4	8
5	9	4	7	8	2	1	6	3
7	8	6	4	1	3	5	9	2

अपना ब्लॉग

महिलाओं को कमांड रोल देना मुश्किल क्यों

मोहन। 'महिला एक मां होती है', 'उस पर परिवार और बच्चे की जिम्मेदारी होती है', 'युद्ध में कुछ भी हो सकता है', 'कहीं युद्धबंदी बना लिया तो?' ये ही वे मुख्य तर्क हैं जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि भारतीय सेना में अभी महिलाओं को कमांड रोल नहीं दिया जा सकता। कमांड रोल यानी सेना की किसी टुकड़ी का नेतृत्व। सेना में आजकल चल रही यह बहस महिलाओं को देखने के नजरिये से जुड़ी कई चीजें साफ करती है। महिलाओं को कमांड रोल देने में कई प्रैक्टिकल दिक्कतों का भी हवाला दिया जा रहा है। सियाचिन जैसे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वहां एक छोटी सी जगह में कमांडर को अपने जवानों के साथ रहना होता है। पानी नहीं है तो मुश्किल से हफ्ते में एक बार स्क्रब करने लायक पानी मिल पाता है। लंबी–लंबी पेट्रोलिंग में जाना होता है। महिलाएं ये सब कैसे कर पाएंगी? सवाल पहली नजर में जंच सकता है, लेकिन सेना का काम तो टफ होता ही है। सेना में भर्ती होने से पहले पुरुषों को भी पता होता है कि यह कोई आसान काम नहीं, जान तक जाने का डर बना रहेगा।